RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 13 SEPTEMBER TO 19 SEPTEMBER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 52 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

हिंडाल्को ने इटली की कंपनी मेट्रा से किया करार
Page 3

GST को लेकर आया नया अपडेट 1 नवंबर से बदल जाएगा ये नियम
Page 4

देश में बना भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर
Page 7

editoria!

सुरक्षा परिषद की सदस्यता

दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे को भी बल मिला है. सम्मेलन के लिए आये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने भारत की सदस्यता की मांग का समर्थन किया है. जी-20 के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी वैश्विक संस्थाओं में दुनिया की नयी वास्तविकता की झलक होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो समय के साथ नहीं बदलते, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है. उन्होंने कहा कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तब दुनिया बिल्कुल अलग थी और केवल 51 सदस्य इससे जुड़े थे, और अब यह संख्या बढ़कर लगभग 200 तक पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री ने जिस वास्तविकता की बात की है. उसे भारत ने जी-20 सम्मेलन में बड़े प्रभावी तरीके से सिद्ध किया है. भारत ने आजादी के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से अलग पहचान बनाये रखी है. उसने वर्तमान सदी में दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत का भी अहसास कराया है. लेकिन, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अभी तक भारत को विकासशील देश होने की वजह से दूसरी कतार में रखा जाता रहा है, और वहां विकसित देशों का वर्चस्व रहा करता है. जी-20 के आयोजन से भारत ने साबित कर दिया है कि वह हमेशा दूसरे देशों से सीख लेते रहने की जगह, अब खुद भी अपने नेतृत्व में वैश्विक एजेंडा तय करवा सकता है. दिल्ली पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत के महत्व को स्वीकार किया है और संगठन में सुधार को जरूरी बताया है. लेकिन, उनका कहना है कि भारत को स्थायी सदस्यता देने का फैसला परिषद के सदस्य ही कर सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत की मांग का समर्थन करते हैं. भारत की स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ी रुकावट चीन रहा है. मगर, जी-20 सम्मेलन में चीन ने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्वीकार्यता को महसूस कर सहयोग किया है, जिसका सबूत सर्वसम्मति से तैयार हुआ घोषणापत्र है. भारत ने दिल्ली में जिस प्रकार से यूक्रेन -रूस संघर्ष से बंटी दुनिया में सहमति करवायी है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद में उसकी मौजूदगी से वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी.

सरकार का बड़ा फैसला

बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम के लिए 3,760 करोड़ का फंड हुआ मंजूर

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए बुधवार को 3,760 करोड़ रुपये के व्यवहार्यता अंतर कोष (VGF) को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना से संबंधित 3,760 करोड़ रुपये की समूची राशि का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह कोष वर्ष 2030-31 तक पांच किस्तों में जारी किया जाएगा। इससे 4,000 मेगावाट घंटे का ऊर्जा भंडार तैयार करने में मदद मिलेगी।

ठाकुर ने कहा कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण से 9,500 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भंडारण प्रणाली की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के वास्ते 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को भी बुधवार को मंजूरी दी। वर्ष 2028-29 तक 774 पंजीकृत इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता थी। अतिरिक्त फंड इसलिए मंजूर किया गया है, क्योंकि अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 के दौरान 131.90 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय समाप्त हो गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, '2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के आवंटन के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी गई थी।' फैसले के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत 774 इकाइयां रजिस्टर्ड थीं और अतिरिक्त धनराशि उन्हें दी जाएगी। इन इकाइयों ने करीब 49,000 रोजगार के सृजन में मदद की है। सरकार इन दोनों राज्यों में निवेश के लिए कंपनियों को योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों में ऋण और बीमा तक पहुंच शामिल है।

G20 समिट में बने बायो फ्यूल अलायंस से पैदा होंगे 500 अरब डॉलर के मौके

नई दिल्ली । एजेंसी

भारतीय बायोगैस असोसिएशन का मानना है कि बायो फ्यूल अलायंस अगले तीन साल में G20 देशों के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर पैदा कर सकता है। आईबीए ने कहा कि अलायंस G20 देशों के साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी फायदे का सौदा साबित होगा। आईबीए के रिसर्च में बताया गया है कि अन्य ऊर्जा विकल्पों की तुलना में बायो फ्यूल उत्पादन में कम निवेश की जरूरत और कच्चे माल की सुगम उपलब्धता रहती है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इससे बड़ी मात्रा में कारोबारी अवसर पैदा हो सकते हैं।

कार्बन उत्सर्जन होगा कम

यह परिवहन क्षेत्र में कॉर्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। साल 2016 में G20 ने नवीकरणीय ऊर्जा पर एक स्वैच्छिक कार्ययोजना को अपनाया था। इसके तहत G20 के सदस्यों को अपनी कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाना था। भारत ने अपने कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई है। पिछले छह साल में यह सालाना 22 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

भारत ने सौर ऊर्जा में किया 20 गुना इजाफा

भारत ने पिछले दशक में सौर ऊर्जा में 20 गुना वृद्धि की है। इस अवधि के दौरान सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की सालाना वृद्धि मोटे तौर पर 38 प्रतिशत और 30 प्रतिशत रही है। इसमें कहा गया है कि बायो फ्यूल उद्योग को गति देने के लिए शुरुआत में 100 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। यानी अगले तीन साल में प्रत्येक उ20 भागीदार को पांच-पांच अरब डॉलर का निवेश करना होगा। आईबीए ने कहा कि बायो फ्यूल अलायंस की सफलता के लिए उ20 भागीदारों के बीच मशीनरी और उपकरणों के हस्तांतरण को आसान बनाया जाना चाहिए।

ग्रीन क्लाइमेंट फंड के लिए ब्रिटेन देगा योगदान

ब्रिटेन ने रविवार को कहा कि वह क्लाइमेट चेंज से निपटने में दुनिया की मदद करने के मकसद से ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के लिए दो अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। भारत में ब्रिटेन के उच्चायोग ने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और उसके अनुसार ढलने में दुनिया के कमजोर लोगों की मदद करने के लिए यह वित्तीय योगदान देने की घोषणा की है। सुनक शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस समय नई दिल्ली में हैं।

PM मोदी बीना रिफाइनरी की 49,000 करोड़ रुपये की विस्तार परियोजना की रखेंगे आधारशिला

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बीना में स्थित बीपीसीएल रिफाइनरी की 49,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस परियोजना को वित्तीय प्रोत्साहन, ब्याज-मुक्त कर्ज और रियायती दरों पर बिजली के अलावा स्टाम्प शुल्क में छूट दे रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी बीना रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता को 78 लाख टन से बढ़ाकर 1.1 करोड़ टन तक पहुंचाने की योजना बनाई है. इस परियोजना के तहत 2,200 किलोटन पेट्रोरसायन उत्पादों के भी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पेट्रोरसायन परिसर और रिफाइनरी विस्तार की यह परियोजना पांच साल में पूरी हो जाएगी। एथिलीन क्रैकर परिसर में रिफाइनरी से निकलने वाले नैफ्था, एलपीजी और केरोसिन जैसे उत्पादों का इस्तेमाल किया जाएगा। बयान के मुताबिक, यह पेट्रोरसायन परिसर प्लास्टिक, पाइप, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक शीट, वाहन कलपुर्जे, चिकित्सा उपकरण, मोल्डेड फर्नीचर और घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विनिर्माण इकाइयों की संभावनाएं खोलेगा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य-जीएसटी रिफंड, ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी सहायता, रियायती बिजली और स्टांप शुल्क में छूट के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके परियोजना का समर्थन कर रही है. इसमें कहा गया है, 'डाउनस्ट्रीम उद्योगों, सहायक और सेवा इकाइयों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना होगी।' 'यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा के अनुरूप है, जो भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी।

हिंडाल्को ने इटली की कंपनी मेट्रा से किया करार

भारत में लेटेस्ट एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न टेक्नोलॉजी लाने की है योजना
रेल डिब्बों के निर्माण में एक्सट्रूडर एल्यूमीनियम की भूमिका है अहम

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम रोलिंग और रीसाइक्लिंग कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्ट्रक्चर्ड और वैल्यू एडेड एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न के उत्पादन के लिए इस क्षेत्र की विशेषज्ञ इटली की प्रसिद्ध मेट्रा एसपीए के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में हाई-स्पीड एल्यूमीनियम रेल कोचों के निर्माण के लिए बड़े आकार के एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के उत्पादन को सुनिश्चित करना है। यह भारत सरकार की बेहतर डोमेस्टिक मन्युफैक्चारिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लक्ष्य को सफल बनाने में हिंडाल्को की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है।

एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग में हिंडाल्को के लम्बे अनुभव और एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न, मशीनिंग और वेल्डिंग में मेट्रा की अत्याधुनिक जानकारी को एक साथ लाकर, यह साझेदारी विश्व स्तरीय तकनीक को भारत में लाने के लिए एक ठोस कदम है जो वर्तमान में सिर्फ यूरोप, चीन, जापान और कुछ अन्य देशों के पास ही है। हिंडाल्को का यह गठबंधन दुनिया के सबसे बड़ा रेल नेटवर्क चलाने वाले भारतीय रेलवे के अपग्रेडेशन प्रोग्राम नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में मदद करता है।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पई ने कहा, 'भारत में पैसेंजर ट्रेनों के लिए एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न के एक नए युग की शुरुआत हो रही है इसके लिए मेट्रा के साथ जुड़कर हमें बहुत खुशी हो रही है। कॉमर्शियल वाहनों, मालवाहक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और पैसेंजर ट्रेन एप्लीकेशन में उपयोग होने वाले एल्यूमीनियम का उत्पादन हमारी क्षमता के अनुरूप है। दोनों कंपनियों की विशेषज्ञता इन ट्रेनों की एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी और भारतीय रेल उद्योग के लिए नए मानक स्थापित करेगी।'' मेट्रा एसपीए के सीईओ एनरिको ज़म्पेट्री ने कहा, 'हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी वैश्विक स्तर पर हमारी एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न तकनीक की क्षमताओं को दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। एक साथ मिलकर, हम भारत में हाई-स्पीड ट्रेन निर्माण के लिए एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न को एक नया आकार देने के लिए तैयार हैं, जिससे इस क्षेत्र को शानदार इटालियन एक्सपरटाईज़ और भारतीय बाजार का ज्ञान मिल सकेगा।'

भारतीय रेलवे रेल लाइनों और स्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उच्च गति वाले वातानुकूलित गाड़ियों के निर्माण में एक डायनेमिक मेकओवर की शुरुआत करने जा रहा है। आरामदायक और तेज यात्रा के लिए पहचानी जाने वाली वर्ल्ड क्लास ट्रेन वंदे भारत रेल परिवहन के क्षेत्र में भारत के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। 200 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने के लिए डिज़ाइन की गई यह शानदार ट्रेन का सुचारू रूप से संचालन एल्युमीनियम के उपयोग से ही संभव है। वंदे भारत ट्रेनों के लिए पैसेंजर कोच बनाने के लिए हिंडाल्को ने इस परियोजना में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है यह प्रौद्योगिकी गठबंधन इस प्रयास में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। उच्च गति वाले रेलवे कोचों के निर्माण में मजबूत हाई ग्रेड एल्यूमीनियम अलॉय दुनिया भर में पसंद की जाने वाली मेटल बन गई है, जो अपने हल्के वजन के कारण सुन्दर डिजाइन और अधिक गति देती है। यूरोप, चीन एवं जापान में उपनगरीय मेट्रो सिस्टम, हाई-स्पीड इंटर सिटी और लंबी दूरी की रेल ट्रैफिक की रेल कारों को बनाने के लिए एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है।

बलिया में जमीन के नीचे कच्चे तेल का भंडार होने की संभावना, पुष्टि के लिए ONGC कराएगी सेस्मिक सर्वे

नई दिल्ली। एजेंसी

यूपी के बलिया जिले में नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जमीन के नीचे कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) मौजूद होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) इसकी पुष्टि के लिए सेस्मिक सर्वे व थ्रीडी मैपिंग कराएगी। उसके बाद आगे की जांच होगी। सेस्मिक सर्वे करने वाली कंपनी के प्रभारी राहुल चावला ने बताया कि सेस्मिक सर्वे से जमीन के अंदर तेल मिलने की पुष्टि नहीं होती। हमारी कंपनी ओएनजीसी द्वारा बताए गए डाटा को इकट्ठा कर सौंप देती हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक उसकी जांच करते हैं। हमारी टीम अभी आ रही है। आगे जो आदेश होगा, उस पर काम किया जाएगा।

अल्फा जिओ कम्पनी को ठेका मिला

शहर से सटे दरामपुर, मुबारकपुर गांव के समीप सर्वे करने वाली टीम व मजदूर डेरा डाल चुके हैं। कंपनी आधुनिक मशीनों का पूरा सिस्टम लगा रही है। जमीन में ड्रील मशीन से सैकड़ों फिट खुदाई कर उसमें विस्फोट किया जाता है। उससे उठने वाली तरंगों का आधुनिक मशीन से सर्वे कर डाटा इकट्ठा होता है। अल्फा जिओ कम्पनी को ठेका मिला है।

एक साथ कम्पनी सैकड़ों स्थान पर खुदाई करेंगी। इनकी मॉनिटरिंग ओएनजीसी के आला अधिकारी करेंगे। पूर्व में करीब 2020 के आसपास ओएनजीसी ने गंगा, तमसा के तटवर्ती क्षेत्र में सर्वे किया था। जमीन के अंदर विस्फोट कर उठने वाली तरंगों की इकट्ठ किया था। अब उसके आगे का सर्वे होने की बात कही जा रही है। फेफना थाना क्षेत्र के दरामपुर, मुबारकपुर व सागरपाली में ट्रकों से मजदूरों व भूमि ड्रिल में प्रयोग होने वाले मशीनों के साथ कैंप किया है। इंजन व बल्ली व पाइप को दुरुस्त कर रहे हैं। मजदूर कुछ पूछने पर तेल खोजने के लिए जमीन खुदाई की बात कह रहे।

एक खोज ने बदल दी इस देश की किस्मत

छह गुना ग्रोथ, पांच साल में चौगुनी हुई इकॉनमी

नई दिल्ली। एजेंसी

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी कौन है? इसका जबाव है गुयाना। यह देश साल 2018 से ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी है। पिछले पांच साल में इसने 27.14 फीसदी की औसत इकनॉमिक ग्रोथ हासिल की है। साल 2023 में इसकी इकॉनमी 62.3 परसेंट की रफ्तार से बढ़ी और इस साल इसके 38 परसेंट की तेजी से बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक इस साल भारतीय इकॉनमी 6.1 परसेंट की रफ्तार से बढ़ सकती है। यानी गुयाना की इकॉनमी की रफ्तार भारत से छह गुना है।

दक्षिण अमेरिका में नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट पर बसे देश गुयाना की गिनती साल 2015 तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी। लेकिन उसी साल एक्सन मोबिल कॉरपोरेशन (Exxon Mobil Corporation) ने गुयाना से 100 मील दूर तेल के बड़े भंडार खोज निकाले।

इससे गुयाना को सालाना करीब 10 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है और 2040 तक उसके खजाने में 157 अरब डॉलर आ सकते हैं। एक्सन और उसकी पार्टनर कंपनियों ने पिछले साल गुयाना में तेल उत्पादन से 5.8 अरब डॉलर की कमाई की। इसी साल एक्सन ने गुयाना के ऑयल प्रोजेक्ट पर 12.7 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी।

तेल ने बदल दी किस्मत

तेल की खोज ने गुयाना की तस्वीर बदलकर रख दी है। पिछले पांच साल में देश की इकॉनमी का साइज चार गुना बढ़ चुका है। गुयाना की आबादी मात्र आठ लाख है और इसकी तुलना में तेल भंडार काफी बड़ा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गुयाना दुनिया में पर कैपिटा क्रूड प्रॉड्यूसर के रूप में कुवैत को पीछे छोड़ सकता है। गुयाना साउथ अमेरिका का एकमात्र देश है जहां अंग्रेजी बोली जाती है। देश की सरकार ने एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने के लिए कानून बनाया है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा रहा है।

एलन मस्क की टेस्ला 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट्स करेगी भारत से इंपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला इस साल भारत की ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों से 1.7 से लेकर 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो कॉम्पोनेंट खरीदने की तैयारी में है। ये जानकारी वाणिज्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। पिछले साल के मुकाबले टेस्ला अपने इंपोर्ट को डबल करने जा रही है. पिछले साल टेस्ला ने एक बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब ऑटो पार्ट्स भारत से इंपोर्ट किया था।

पीयूष गोयल ने ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन (ACMA) के सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि टेस्ला द्वारा किया जाने वाला इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले दोगुना रहने वाला है। उन्होंने बताया कि टेस्ला ने पिछले साल एक बिलियन डॉलर का ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट किया था। लेकिन मौजूदा साल में कंपनी अपने इंपोर्ट को बढ़ाकर 1.7 से 1.9 बिलियन करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल ने कहा कि मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य है। उन्होंने कहा कि हमें इसे आकर्षित करना चाहिए। देश के जीडीपी में 2.3 फीसदी हिस्सेदारी स्थानीय

ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडस्ट्री का है. 2025 तक ऑटो कॉम्पोनेंट्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर होगा। टेस्ला भारत में निवेश करना चाहती है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट पर अभी 100 फीसदी टैक्स लगता है। टेस्ला भारत में निवेश से पहले इसे घटाने की मांग कर रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का कोई इरादा नहीं है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। एलन मस्क ने मुलाकात के बाद दिए बयान में कहा था कि कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं टेस्ला भारत में निवेश करे. उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही इस बारे में घोषणा करेंगे। बीते कई सालों से टेस्ला और भारत सरकार के बीच टेस्ला के निवेश को लेकर बातचीत होती आई है। एलन मस्क टेस्ला की भारत में टेस्ला फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, पर टेस्ला ने इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में छूट की मांग की है। भारत सरकार उसकी मांग को खारिज करती रही है।

लोन चुका दिए लेकिन प्रॉपर्टी के कागजात वापस नहीं मिले

बैंक को भरना होगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

होम लोन, कार लोन पर्सनल लोन या गोल्ड लेने वाले व्यक्तियों के साथ अक्सर ऐसा वाकया सुनने

को मिलता है। आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन से लोन लिया है। बदले में अपनी चल-अचल संपत्ति को गिरवी रखा है। आपने इस लोन की पाई-पाई का भुगतान कर दिया है। लेकिन आपने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी के जो कागजात जमा कराए थे या जो चल संपत्ति गिरवी रखी थी, वह वापस नहीं मिल रहा है। इस पर रिजर्व बैंक सख्त हो गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों और Regulated Entities (REs) ने 30 दिन के अंदर इसे वापस करने का निर्देश दिया है। नहीं तो उसे हर दिन की 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

क्या है रिजर्व बैंक का निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज यानी 13 सितंबर को जारी एक निर्देश सभी बैंकों सहित विनियमित संस्थाओं (आरई) को भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही लोन का पूर्ण भुगतान हो जाता है, बैंक सभी चल-अचल संपत्ति के मूल कागजात लोन लेने वालों को 30 दिन के अंदर वापस करे। नहीं तो, जितने दिनों की देरी होगी, 5,000 रुपये रोज के हिसाब से बोरोअर को जुर्माना अदा करना होगा। यह निर्देश पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन समेत वैसे लोन अकाउंट पर लागू होगा, जिसे लेने के लिए बोरोअर ने अपनी चल-अचल संपत्ति को गिरवी रखा है।

क्यों हुई आरबीआई की सख्ती

रिजर्व बैंक का कहना है कि लोन चुका देने के बाद भी बोरोअर को रेहन रखे कागजात समय पर नहीं मिल रहे हैं। ग्राहकों और बैंक के बीच इस बारे में शिकायतें बढ़ रही हैं। इसिलिए रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करना पड़ा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब लोन की पाई-पाई चुका दी गई है तो बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन को 30 दिनों के भीतर सभी कागजात लौटा देना होगा। साथ ही किसी रजिस्ट्री के पास यिद कोई चार्ज लॉज किया गया है तो उसे भी रिमूव करना होगा।

कागजात कहां मिलेगा

लोन लेने वालों को यह विकल्प रहेगा कि वह चल-अचल संपत्ति के कागजात कहां से ले। बोरोअर ये कागजात या तो लोन लेने वाली शाखा से प्राप्त करेगा या फिर वह अपनी सुविधा के हिसाब से किसी अन्य शाखा से कागजात ले सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है इस बारे में लोन के सेक्शन लेटर में भी जिक्र होगा कि कागजात कहां से वापस होंगे।

जब बोरोअर या को-बोरोअर की मृत्यु हो जाती है

रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि एकल उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो आरईएस के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल और अचल संपत्ति दस्तावेज वापस करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली होनी चाहिए। यह नीति, ग्राहक जानकारी से संबंधित अन्य संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ, आरईएस की वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए।

कितना देना होगा जुर्माना

जब मूल चल या अचल संपत्ति दस्तावेज ऋण चुकौती या निपटान के 30 दिनों के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं या उपयुक्त रजिस्ट्रार के पास चार्ज सटिसफेक्शन फार्म जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक को देरी के बारे में बोरोअर को बताना आवश्यक होता है। यदि बैंक को देरी के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करके अंतर को पूरा करना होगा।

GST को लेकर आया नया अपडेट

1 नवंबर से बदल जाएगा ये नियम

नयी दिल्ली। एजेंसी

बड़े कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटी को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नवंबर से माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर 'अपलोड' करना होगा। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा।

जीएसटी के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी है। इसके मुताबिक, प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। 1 नवंबर से लागू होगा नियम

यह समयसीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी। यह व्यवस्था एक नवंबर, 2023 से लागू हो जाएगी।

CBIC सभी कारोबारियों पर लागू कर सकता है

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है।

केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर से मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। ये वो 800 लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा, जिन्हें सरकार 10 लाख रुपये तक की राशि देगी। स्कीम के तहत 1 करोड़ का बंपर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा। ये इनाम दो लोगों को दिया जाएगा।

उमंग स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस कार्यक्रम' के तहत

जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी और प्राचार्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीवन कौशल शिक्षा 'उमंग स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस कार्यक्रम' के अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला इंदौर एवं उज्जैन संभाग जनजातीय कार्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं सी.एम.राईस विद्यालय के प्राचार्यों हेतु इंदौर में दिनांक 12 सितम्बर 2023, को आयोजित हुई ध कार्यक्रम का शुभारंभ श्री. ब्रजेश पाण्डेय, उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, इंदौर संभाग द्वारा किया गया। उनके उद्बोधन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु जीवन कौशल शिक्षा कर्क्रम उमंग के महत्व पर ज़ोर दिया गया तथा सभी स्कूलों में कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

श्री अनुराग सोनवलकर, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, यूएनएफपीए, भोपाल व श्रीमती अंजली अग्रवाल, निदेशक, बीजीएमएस द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा व विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि 'उमंग स्कूल हेल्थ व वैलनेस कार्यक्रम' आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत, स्कूल शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूएनएफपीए व उसकी सहयोगी संस्था बीजीएमएस के सहयोग से प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।

किशोरावस्था जीवन का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन की अत्यंत आवयश्कता होती है ध उमंग जीवन कौशल कार्यक्रम विद्यार्थियों को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनता है व उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। एक दिवसीय कार्यशाला में उमंग कार्यक्रम के संचालन के विषय में विस्तृत चर्चा हुई व कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ करने हेतु ज़िला अधिकारियों व प्राचार्यों की भूमिका को चिन्हित कर कार्य योजना विकसित की गई।

SEBI के इन नियमों से ब्रोकर्स की आफत, बदलाव की सिफारिश

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

बाजार नियामक सेबी ने क्लाइंट के पैसों को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास भेजने और इसे क्लाइंट के पास लौटाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब इन नए नियमों को लेकर ब्रोकर्स को दिक्कत हो रही है। ब्रोकर्स के मुताबिक इससे कारोबार करने में दिक्कतें आ रही है। जानिए सेबी के किन नियमों से ब्रोकर्स को दिक्कत आ रही है और क्या है।

बाजार नियामक सेबी ने क्लाइंट के पैसों को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास भेजने और इसे क्लाइंट के पास लौटाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब इन नए नियमों को लेकर ब्रोकर्स को दिक्कत हो रही है। ब्रोकर्स के मुताबिक इससे कारोबार करने में दिक्कतें आ रही है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम (BBF) नियमों में ढील के लिए बाजार नियामक सेबी के पास पहुंचे हैं। सेबी ने नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के पैसों का गलत इस्तेमाल न कर सकें।

क्या है SEBI का नया नियम

एसोसिएशन के मुताबिक प्रत्येक कारोबारी दिन शाम 6:30 बजे से पहले क्लाइंट्स के फंड की अपस्ट्रीमिंग अनिवार्य करने के साथ-साथ हर दिन का हिसाब- खिताब भेजने के नियम से ब्रोकर्स को अधिक मैनपावर और पूंजी लगानी पड़ रही है। यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू है। सेबी के नियम के मुताबिक ब्रोकर्स को क्लाइंट्स से फंड पहले अप स्ट्रीमिंग क्लाइंट नोडल बैंक अकाउंट (USCNBA), फिर इसके बाद सेटलमेंट, फिर सेटलमेंट से क्लियरिंग कॉरपोरेशन, फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन से सेटलमेंट, फिर सेटलमेंट से DSCNBA (डाउन स्ट्रीमिंग क्लाइंट नोडल बैंक अकाउंट) से क्लाइंट्स के खाते में फंड भेजने की कई चरणों की लंबी प्रक्रिया से दिक्कत है।

इससे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अकाउंट्स एक ही होता था और इसे ब्रोकर का क्लाइंट अकाउंट कहते थे। पैसों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नया नियम लाया गया कि USCNBA और DSCNBA, दोनों को हर दिन खाली करना होगा। इसमें से USCNBA को शाम 6:30 बजे तक और DSCNBA को दिन के आखिरी तक खाली करना होगा। ये फंड्स सिर्फ क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास रह सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ब्रोकर्स को कट ऑफ टाइम को लेकर है जिसके चलते उनका मानना है कि ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं और क्लाइंट सर्विसिंग प्रोसेस पर असर पड़ रहा है।

दिल्ली के एक ब्रोकिंग फर्म के एग्जेक्यूटिव का कहना है कि ब्रोकर्स का कई बैंकों में अपस्ट्रीमिंग अकाउंट होता है ताकि क्लाइंट से ब्रोकर के पास आसानी से फंड ट्रांसफर हो जाए। अब ब्रोकिंग फर्म का कहना है कि अगर किसी बैंक में तकनीकी खामी आ जाए और फंड समय पर ट्रांसफर न हो पाए तो इसमें ब्रोकर्स को क्यों जवाबदेह माना जाए? क्लाइंट के पैसों के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यानी क्लाइंट से क्लियरिंग कॉरपोरेशन और क्लियरिंग कॉरपोरेशन से क्लाइंट के पास पैसे ट्रांसफर करने के मामले में 10 करोड़ रुपये से ऊपर के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये की पेनाल्टी का प्रावधान सेबी ने किया है।

इसके अलावा सेबी के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी क्लाइंट ने शाम 6 बजे तक पैसे निकालने की रिक्वेस्ट कर दी है तो उसी दिन ब्रोकर्स को इसे प्रोसेस करना होगा। हालांकि ब्रोकर्स के मुताबिक इसमें डीएलोकेशन, रिलीज, क्लियरिंग मेंबर/ ब्रोकर की तरफ से इंटर-बैंक ट्रांसफर और क्लाइंट के खाते में पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो काफी लंबा है। ब्रोकर्स को एक और नियम से दिक्कत है जिसके तहत उन्हें रीजन कोड देने की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर्स का कहना है कि छोटी-छोटी डिटेल्स और माइक्रो-मैनेजमेंट के चलते ऑपरेशनल लेवल पर दिक्कतें बढ़ गई हैं।

ब्रोकर्स की क्या है सिफारिश

ब्रोकर्स फोरम ने सेबी से अनुरोध किया है कि क्लियरिंग मेंबर्स ने जो आंतरिक नीति बनाई है, उसके आधार पर क्लाइंट्स के खाते में पैसे भेजने की जरूरतों को तय किया जाए। इन नीतियों को इन क्लियरिंग मेंबर्स की साइट पर दिखाया जा सकता है। मुंबई के एक ब्रोकर ने इसे समझाते हुए बताया कि पहले पुराने डेटा के आधार पर ब्रोकिंग फर्म ब्रोकर्स क्लाइंट अकाउंट से पैसे काट लेती थी यानी नेट ऑफ कर देती थी और बाकी को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास ट्रांसफर कर देती थी लेकिन अब नेटिंग पर रोक लग गई है और क्लाइंट के पूरे पैसों को अपस्ट्रीम करना होता है। पेआउट यानी क्लाइंट की पैसे निकालने की रिक्वेस्ट भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास कट-ऑफ समय से कम से कम एक घंटे पहले पहुंचना होता है। इसके बाद ही आगे का प्रॉसेस बढ़ता है। इस प्रक्रिया में किसी भी लेवल पर तकनीकी खामी आ सकती है।

बिना कार्ड से ATM से निकलेंगे पैसे

आनंद महिंद्रा बोले-ये तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए खतरे की घंटी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत तरक्की के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर तकनीक के मामले में देश ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले आप बैंक जाकर लाइन लगाकर अपने खाते से कैश निकालते थे, फिर ऊश मशीन आई। कुछ ही मिनट में बिना बैंक गए एटीएम मशीन से कैश निकलने लगा। अब देश एक और कदम आगे बढ़ गया है. आप बिना एटीएम कार्ड के भी अपने बैंक खाते से कैश निकाल सकते हैं। भारत की इस तरक्की को देखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन काफी खुश हैं।

UPI ATM देखकर आनंद महिंद्रा भी हुए हैरान

एटीएम से पैसा निकालने के लिए अब आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। देश का पहला वाइट लेवल यूपीआई-एटीएम (UPI-ATM) लॉन्च हो चुका है। आप बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकेंगे। आनंद महिंद्रा ने इस नई सर्विस की तारीफ करते हुए लिखा कि जिस रफ्तार से भारत की डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेस बढ़ रही है, वो तारीफ के काबिल है। डिजिटल सर्विस अब कॉरपोरेट केंद्रित होने के बजाए कंज्यूमर केंद्रित बन रहे हैं।

क्रेडिट कार्ड कंपनियों की बढ़ेगी टेंशन

आनंद महिंद्रा ने लिखा कि यूपीआई एटीएम का नया अविष्कार क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए नई टेंशन बन सकता है। महिंद्रा ने यूपीआई एटीएम सर्विस की तारीफ करते हुए लिखा कि बस ध्यान इस बात का रखना है कि मैं अपना मोबाइल फोन कहीं भी न भूल जाऊं। दरअसल हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकते हैं। आनंद महिंद्रा ने इसका वीडियो भी ट्वीट किया है। जिसमें एक शख्स बता रहा है कि कैसे यूपीआई के जरिए कैसे एटीएम से कैश निकाल सकते हैं।

कैसे काम करता है यह

UPI ATM के जरिए नकदी निकालने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पर यूपीआई का चुनाव करना है, एटीएम पर राशि चुनकर चुनी हुई राशि से जुड़ा यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करना है। मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपको यूपीआई ऐप का ऑप्शन और बैंक अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा । लेनदेन की पुष्टि के लिए अपना यूपीआई पिन डालें। आपका कैश बाहर आ जाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी यूपीआई इनेबल ऐप है तो आप यह कर सकेंगे।

शेखों के देश सऊदी अरब में ये भारतीय लगा रहे हैं पैसा

नई दिल्ली। एजेंसी

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हाल में जी-20 देशों के समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत थे। इस समिट के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें खासकर एनर्जी के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हुए हैं। भारत कई दशकों से सऊदी अरब से कच्चे तेल (Crude) और एलपीजी (LPG) का आयात करता रहा है। लेकिन अब भारत से सऊदी अरब को एनर्जी एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक अंडरसी केबल बिछाने की भी योजना है। इसके जरिए भविष्य में सऊदी अरब को बिजली, रिन्यूएबल पावर और ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही भारत की कई कंपनियां बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के एनर्जी सेक्टर में निवेश की तैयारी कर रही हैं। सऊदी अरब में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दो बड़े समझौते हुए हैं। पहला समझौता विनीत मित्तल की अगुवाई वाली अवाडा एनर्जी और सऊदी अरब की कंपनी एईडब्ल्यू के बीच हुआ है। दूसरा समझौता रुइया प्रमोटेड एस्सार ग्रुप और सऊदी अरब की कंपनी डेजर्ट टेक्नोलॉजीज के बीच हुआ है। एस्सार ग्रुप सऊदी अरब में 4.5 अरब डॉलर की लागत से एक ग्रीन स्टील प्लांट बना रहा है। अवाडा ग्रुप ने सऊदी अरब के साथ-साथ मध्य पूर्व के कुछ और देशों में भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है।

अवाडा ग्रुप

ग्रीन एनर्जी डेवलपर कंपनी अवाडा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल का कहना है कि सऊदी अरब की कंपनी के साथ अलायंस से सोलर, विंड, हाइब्रिड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में नई संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे। समझौते के मुताबिक अवाडा टेक्नोलॉजी पार्टनर का काम करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस के लिए सॉल्यूशन देगी। दूसरी ओर एईडब्ल्यू इसके लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी। अवाडा भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और सौर उपकरण मैन्युफैक्चरिंग की नई परियोजनाएं लगाने की योजना बना रही है।

दूसरी ओर रुइया बंधुओं के निवेश वाले एस्सार ग्रुप सऊदी अरब में 4.5 अरब डॉलर के निवेश से इंटिग्रेटेड ग्रीन स्टील प्लांट बना रहा है। कंपनी ने इसके लिए सऊदी अरब की सोलर फोटोवोल्टिक कंपनी डेजर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियां एस्सार के फ्लैट स्टील कॉम्प्लेक्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन और स्टोरेज सॉल्यूशन विकसित करेंगी। यह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (उण्ण) रीजन में पहला ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट है। इससे 2027 में प्रॉडक्शन शुरू होने की उम्मीद है।

एस्सार का कारोबार

रवि रुइया और शशि रुइया ने मिलकर साल 1969 में एस्सार ग्रुप की शुरुआत की थी। ग्रुप का बिजनस स्टील, ऑयल एंड गैस, पावर, कम्युनिकेशन, शिपिंग एंड मिनरल्स के सेक्टर में फैला है। 20 से अधिक देशों में इसका विस्तार है। ग्रुप में 75000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इसका रेवेन्यू करीब 17 अरब डॉलर है। साल 2012 में फोर्ब्स ने रुइया ब्रदर्स को वर्ल्ड रिचेस्ट इंडियन की रैंकिंग दी थी। उस वक्त उनका नेटवर्थ 7 अरब डॉलर था।

इंडिया Vs भारत विवाद के बीच ब्लू डार्ट का बड़ा फैसला, अपने नाम क साथ जोड़ा 'भारत'

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सियासी गलियारे में इंडिया बनाम भारत का विवाद लगातार तेज हो रहा है। नाम पर बढ़ते इस विवाद के बीच बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी ब्लू डार्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्लूडार्ट ने अपना नाम बदल दिया है। ब्लूडार्ट का नाम बदलकर अब भारत डार्ट कर दिया है। कंपनी ने अपनी प्रीमियम सेवा डार्ट प्लस का नाम बदलकर भारत डार्ट कर दिया है। बता दें कि कंपनी ने सिर्फ अपनी प्रीमियम सर्विस डार्ट प्लस का नाम बदला है। अब इस सर्विस को 'भारत डार्ट' के नाम से जाना जाएगा। कंपनी के नाम बदलने के फैसले को इंडिया बनाम भारत के बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। नाम बदलने के अपने फैसले को लेकर कंपनी ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबंद्धता बताई। कंपनी ने कहा कि हम भारत को पूरी दुनिया और दुनिया को भारत से जोड़ते है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि उनका ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। ब्लू डार्ट का यह कदम भारत बनाम इंडिया के बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने बयान में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड अपने सभी शेयरधारकों को इस बदलाव को स्वीकार करने की अपील की है। कंपनी ने नाम बदलने के इस फैसले की जानकारी शेयर बाजार को दी है। गौरतलब है कि जी20 के दौरान 9 सितंबर को भारत मंडपम में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित होने वाले डिनर के इन्विटेशन में 'द प्रेसिडेंट ऑफ भारत' के नाम ने न्यौता भेजा गया। इनवाइट पर छपे 'भारत' शब्द के बाद इंडिया बनाम भारत की बहस शुरू हो गई। जी20 सम्मेलन के दौरान भी हर जगह 'भारत' शब्द को प्राथमिकता दी गई। इसे लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हमले जारी है।

देश में बना भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर

3 लाख स्क्वायर मीटर इनडोर एरिया, जानिए कितनी आई लागत

नई दिल्ली । एजेंसी

जी20 के दौरान दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र प्रगति मैदान का भारत मंडपम बना रहा। अब इस सम्मेलन के तुरंत बाद भारत मंडपम से भी बड़ा इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर तैयार हो चुका है। यह नई दिल्ली के द्वारका में है। सितंबर के तीसरे हफ्ते तक पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अक्टूबर के लिए कन्वेंशन सेंटरों के आयोजन के लिए यहां आवेदन लेना भी शुरू कर दिया गया है। आईआईसीसी द्वारका का पहला फेज तैयार है।

17 सितंबर को हो सकता है लॉन्च

जानकारी के अनुसार, 17 सितंबर के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी इसकी आधिकारिक शुरुआत कर सकते हैं। करीब 25,703 करोड़ रुपये की लागत से तैयार आईआईसीसी में ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस, होटल रूम के अलावा एग्जीबिशन हॉल और कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसके शुरू होने के बाद जी20 जैसे बड़े आयोजन यहीं किए जा सकते हैं। इसे प्रगति मैदान का विकल्प माना जा रहा है।

6000 लोगों के बैठने की क्षमता

आईजीआई एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आईआईसीसी दो फेज में तैयार हो रहा है। पहला फेज तैयार है। पहले फेज में मेगा कन्वेंशन सेंटर, दो एग्जीबिशन हॉल और 3000 गाड़ियों की पार्किंग शुरू होने वाली है। अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, यहां बन रहा मल्टीपर्पस कन्वेंशन सेंटर देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यहां पर 6000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इनमें दो ग्रैंड बॉलरूम भी शामिल हैं, जिनकी 2400 सीटिंग कपैसिटी है। इसके अलावा, 13 अन्य मध्यम और बड़े साइज के कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। दोनों एग्जीबिशन हॉल करीब 54000 स्क्वायर मीटर की जगह में बने हैं। इनमें 1800 एग्जीबिशन बूथ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बाहरी जगह भी यहां उपलब्ध है।

कुल इनडोर एरिया 300,000 स्क्वायर मीटर

इसके फेज-2 में तीन एग्जीबिशन हॉल के अलावा एक एरेना भी होगा। दोनों फेज तैयार होने के बाद आईआईसीसी का कुल इंडोर एरिया 300,000 स्क्वायर मीटर होगा। पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स होगा। अधिकारी के अनुसार, यहां एक किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 3500 गेस्ट रूम उपलब्ध होंगे। साथ ही शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिस की सुविधा भी होगी। इसलिए यह ऑर्गनाइजर, एग्जीबिशन और बायर्स के लिए भी आयोजन की उपयुक्त जगह होगी। किनेक्सिन कन्वेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इस वेन्यू के ऑपरेटर के तौर पर 20 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। कंपनी ने 23 से 25 तक आयोजनों की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, लॉन्च के दिन इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम भी बदला जा सकता है। जिस तरह से जी20 आयोजन के तहत भारत को प्रमोट किया गया, इसके नाम से भी इंडिया हटाकर भारत जोड़ा जा सकता है।

जो बाइडेन की डिप्लोमेसी का असर शुरू, अमेरिकी सेब और अखरोट पर कम हुआ टैक्स

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका से आने वाले सेब पर लगने वाले एडिशनल ड्यूटी को हटाने के सरकार के फैसले से हंगामा मच दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सेब किसान नाराज हैं। सरकार के इस फैसले की आलोचना हो रही है, जिसके बाद वाणिज्य मंत्रालय क ओर से सफाई दी गई है। सरकार का कहना है कि वाशिंगटन सेब पर एडिशन ड्यूटी खत्म करने से भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस निशाना साध रही है कि सरकार ने अमेरिका को उपहार में अमेरिकी सेब (वाशिंगटन एपल) पर आयात शुल्क को 70 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड किसानों को बड़ा नुकसान होगा। सरकार ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम के आयात पर अतिरिक्त जवाबी शुल्क हटाने से घरेलू उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी दल खासकर कांग्रेस विषय की पूरी समझ के बिना ही इस विषय का राजनीतिकरण कर रही है। सेब पर 50 प्रतिशत का नियमित शुल्क और 50 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य है। उन्होंने कहा कि हमने अभी जवाबी शुल्क हटा दिया है...इस कदम का घरेलू सेब उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमतों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे।

इससे पहले वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव पीयूष कुमार ने कहा कि अमेरिकी सेब और अखरोट पर 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत का 'सबसे तरजीही देश' (एमएफएन) का शुल्क लागू रहेगा क्योंकि केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है। उन्होंने कहा कि सेब, अखरोट और बादाम पर एमएफएन शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अब भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर लागू है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस उपाय से घरेलू सेब, अखरोट और बादाम उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि, इसके परिणामस्वरूप सेब, अखरोट और बादाम के प्रीमियम बाजार खंड में प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे हमारे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अमेरिकी सेब और अखरोट के आयात पर अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाने से अन्य देशों को लाभ होने के कारण अमेरिकी सेब की बाजार हिस्सेदारी घट गई।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त शुल्क हटाने से अब उन देशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी जो भारत को इन उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। यह स्पष्टीकरण विपक्षी कांग्रेस द्वारा सेब पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के फैसले की आलोचना के बीच आया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र ने वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जिसका सीधा असर बागवानों पर भी पड़ेगा, जिससे उन्हें नुकसान होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को केंद्र से अमेरिका से आयातित सेब, अखरोट और बादाम पर अतिरिक्त शुल्क हटाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को विदेशियों को खुश करने के बजाय अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए।

'मेक इन इंडिया' के मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मेक इन इंडिया के मुरीद हो गए हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के लिए लोगों को प्रेरित करके प्रधानमंत्री मोदी सही काम कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए रूसियों को घरेलू स्तर पर बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के एक प्रोग्राम में पुतिन ने कहा कि भारतीय लोग अब गाड़ियां और जहाज खुद बनाने लगे हैं, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। पुतिन ने भारत मध्य-पूर्व यूरोप इकोनॉमिक फोरम पर भी टिप्पणी की।

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की हो। इसी साल जून के महीने में भी पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी तारीफ की थी। पुतिन ने मेक इन इंडिया की तारीफ करते हुए कहा था कि इससे भारत को फायदा हुआ है।

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें अपने कई भागीदारों या कहें तो भारत से सीखने की जरूरत है। वे ज्यादातर भारत में उत्पादित कारों व जहाजों के उत्पादन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस संबंध में, प्रधानमंत्री मोदी लोगों को मेड इन इंडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके सही काम कर रहे हैं। हमारे पास वे वाहन भी उपलब्ध हैं और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। पुतिन का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब जब यूरोपीय यूनियन ने रूस में बनी कार और दूसरे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है और उन्होंने अपने देश में स्वदेशी कारों को चलाने का कैंपेन चलाया हुआ है।

पीएम मोदी कर रहे शानदार काम

पुतिन ने कहा कि उन्हें लगता है कि अपने कई सहयोगियों के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। कहा कि आप भारत को ही देख लीजिए। अब वहां के लोग कारों के निर्माण और उन्हें इस्तेमाल करने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत बने उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर बिलकुल ठीक काम कर रहे हैं। कहा कि रूस में बनाई गई गाड़ियों का इस्तेमाल करना बिलकुल ठीक है।

कॉरिडोर पर कही ये बात

जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य-पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (घ्ईंं) का ऐलान किया था। इस कॉरिडोर पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि आईएमईसी रूस को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा बल्कि इससे देश को फायदा ही होगा। इससे लॉजिस्टिक्स विकसित करने में मदद मिलेगी।

वास्तु शास्त्र और उसका परिस्थिति अनुसार बदलाव

वास्तु ऊर्जा का प्रभाव परिस्थित अनुसार बदलता है, कॉलोनी डेवेलोप होने से छोटे मकान बनने तक कैसे परिवर्तन आता जाता है, समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई डेवलपर किसी कॉलोनी के लिए जमीन खरीदता है, तभी से इस जमीन की वास्तु ऊर्जा का प्रभाव उस डेवलपर पर शुरू हो जाता है, अर्थात एक जमीन पर शास्त्र के जो- जो नियम लागू होते हैं, उस डेवलपर पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे जमीन का आकार, ढलान, शल्य, जमीन पर छोटे-बड़े टीले, जमीन में मौजूद कुँए, बोरिंग आदि। जलाशय, कोई जिओपेथी ऊर्जा या उसका नोडल पॉइंट, जमीन में मौजूद कोई मंदिर मजार वृक्ष (पीपल, बरगद, नीम आदि), बांबी आदि की ऊर्जा आदि सबका मिलाजुला प्रभाव शुरू हो जाता है। जब इस भूमि पर डेवलपर द्वारा विकास कार्य या निर्माण शुरू किया जाता है, तब निर्माण संबंधी नियम लागू होना शुरू होते जाते हैं। बाउंड्री वाल से एक सीमा सुनिश्चित हो जाती है। दीवार की दिशा अनुसार ऊंचाई मोटाई का प्रभाव होने लगता है। मुख्य द्वार की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। गलत पद में मुख्य द्वार का निर्माण डेवलपर के लिए तो परेशानी पैदा करता ही है। आने वाले समय मे रहवासियों पर भी इसका परिणामिक प्रभाव देखने मे मिलता है। ठीक इसी प्रकार अन्य निर्माण जैसे भूमि के ढलान, सड़कों के ढलान, सेप्टी टैंक, पानी की टंकी, गार्डन, गार्डन आदि में स्थापित सांकेतिक मूर्तियाँ, ड्रेनेज की व्यवस्था, बिजली की ष्ठक्कक्की व्यवस्था आदि सब शास्त्र अनुसार होना लाभकारी होता है । यदि निर्माण में शास्त्र अनुसार दोष छोड़े जाएँ तो शुरुवाती समय मे डेवलपर संबंधित दोषों के प्रभाव में रहता है, फिर जैसे-तैसे जब रहवासी उसमें आने लगते हैं तब सम्पूर्ण कॉलोनी के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अलग-अलग रहवासियों पर भाग्य अनुसार होता है। रहवासी पर दो रूपों में वास्तु ऊर्जा काम करती है, पहली सम्पूर्ण कॉलोनी की ऊर्जा का प्रभाव और दूसरा मुख्य प्रभाव उसके निजी प्लाट या घर का होगा यहाँ अलग-अलग परिस्थिति पर विचार किया जा सकता है।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

1. वास्तु सम्मत बनी कॉलोनी में वास्तु सम्मत बना भवन अधिकतम समृद्धि प्रदान करेगा ।

2. दोषित कॉलोनी में वास्तु सम्मत बना भवन मिलाजुला प्रभाव देगा वह निर्भर करेगा कि कॉलोनी के किस दोषपूर्ण हिस्से में उसका भवन है।

3. यदि कॉलोनी दोषपूर्ण है और निर्मित भवन भी दोषपूर्ण है तब अधिकतम परेशानी । 4. शास्त्र नियम से बनी कॉलोनी है और उस पर दोषपूर्ण भवन का निर्माण किया गया है तब भी उपयोगकर्ता को विविध परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पूर्व में ही बताया है बड़ा प्रभाव भवन का है।

यदि पॉइंट नंबर 1 अनुसार भवन मिल जाये तो सर्वोत्तम है परंतु ऐसा ना भी हो तो कम से कम आप अपने निजी जमीन पर नियमों का अधिकतम पालन कर प्राकृतिक ऊर्जाओं का अधिकतम उपयोग कर ही सकते हैं।

अमावस्या से जुड़ी परंपराएं

अमावसु नाम के पितर की वजह से कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को कहते हैं अमावस, इस दिन करें नदी स्नान और दान

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

हिन्दी पंचांग के एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरों शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की पंद्रहवी तिथि को अमावस कहा जाता है। 14 और 15 सितंबर को भाद्रपद मास की अमावस्या है, इसे कुशग्रहणी अमावस भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को एक पितर की वजह से अमावस नाम मिला है। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप-ध्यान, देवी-देवता की पूजा के साथ ही दान-पुण्य जरूर करें। जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े, जूते-चप्पल, धन का दान करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, शास्त्रों में अमावस्या से जुड़ी एक कथा बताई गई है। कथा ये है कि पुराने समय में एक कन्या ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उस कन्या की तपस्या से पितर देवता प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। उस दिन कृष्ण पक्ष की पंद्रहवी तिथि ही थी। पितरों में एक अमावसु नाम के पितर भी थे, वे दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थे। जब कन्या ने अमावसु को देखा तो वह मोहित हो गई और उसने अपने वरदान में मांगा कि वह अमावसु से विवाह करना चाहती है। कन्या भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अमावसु ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। कन्या ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमावसु नहीं माने। अमावसु के संयम से अन्य सभी पितर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अमावसु को वरदान दिया कि अब से कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि अमावसु के नाम से ही जानी जाएगी। इस कथा की वजह से हर महीने के कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को अमावस, अमावस्या कहा जाने लगा।

चंद्र की सोलहवीं कला है अमा

शास्त्रों में चंद्र की सोलह कलाएं बताई गई हैं और सोलहवीं कला को अमा कहा जाता है। इस तिथि पर सूर्य और चंद्र एक साथ एक ही राशि में स्थित रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि- अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकला। संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी।। इस श्लोक के अनुसार अमा को चंद्र की महाकला गया है, इसमें चंद्र की सभी सोलह कलाओं की शक्तियां रहती हैं। इस कला का क्षय और उदय नहीं होता है।

अमावस्या पर पितरों के लिए जलाएं धूप-दीप

अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इसलिए अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और, धूप-ध्यान और दान-पुण्य करने का महत्व है। अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन मंत्र जाप, तप और व्रत करने की परंपरा है। सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और ऊँ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन शिव मंदिर जाएं और तांबे के लोटे में जल भरकर अभिषेक करें। ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन हनुमानजी के सामने दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

अमावस्या पर करें भगवान विष्णु-लक्ष्मी का अभिषेक

भाद्रपद की अमावस की सुबह देवी-देवताओं की पूजा, दोपहर में पितरों के लिए धूप-ध्यान और शाम को तुलसी के पास जलाएं दीपक

गुरुवार, 14 सितंबर और शुक्रवार, 15 सितंबर को भाद्रपद की अमावस्या है। तिथियों की घट-बढ़ की वजह से दो दिन ये तिथि रहेगी। इसे कुशग्रहणी अमावस कहते हैं, क्योंकि इस दिन साल भर के लिए कुश घास इकट्ठा की जाती है। पूजा-पाठ, धूप-ध्यान के नजरिए से इस अमावस्या का महत्व एक पर्व की तरह ही है। जानिए अमावस्या से जुड़ी खास बातें...

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, अमावस्या पर देवी-देवताओं की पूजा के साथ ही पितरों के लिए धूप-ध्यान, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि शुभ काम जरूर करें।

सुबह देवी-देवताओं की पूजा करें, दोपहर में पितरों के लिए धूप-ध्यान और और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं।

अमावस्या की सुबह जल्दी उठें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। लोटे में पानी के साथ फूल और चावल भी जरूर डालें।

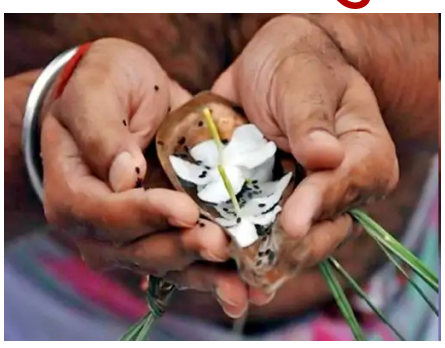

ऐसे कर सकते हैं भगवान का अभिषेक

घर के मंदिर में बाल गोपाल के साथ ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग करें। भगवान का अभिषेक करने के लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय कृं कृष्णाय नमः और ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दूध के बाद जल से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें। इत्र लगाएं। हार-फूल से श्रृंगार करें। चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी के पत्तों के माखन-मिश्री और मिठाई का भोग लगाएं। धूप-दीप जलाकर आरत करें।

दोपहर में करें पितरों के लिए धूप-ध्यान

अमावस्या की दोपहर गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए, तब पितरों का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़-घी डालें। घर-परिवार और कुटुंब के मृत सदस्यों को पितर कहा जाता है। गुड़-घी अर्पित करने के बाद हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों का ध्यान करते हुए जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद गाय को रोटी या हरी घास खिलाएं। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं।

शाम को तुलसी के पास जलाएं दीपक

सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं। ध्यान रखें शाम को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपक जलाकर तुलसी की परिक्रमा करें।

गणपति आराधना के लिए कैसी होनी चाहिए गणेशजी की मूर्ति

सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग अपने शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। माना जाता है की गणेश जी को शिव जी से वरदान मिला था जिसके अनुसार सभी देवी देवताओं से पहले उनकी पूजा अर्चना होती है। इसलिए गणेश की पूजा और मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व है। गणेश जी को सुख समृद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इस वर्ष भाद्रशुक्ल चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को है। इस दिन घर में मंगल कामना और सुख के लिए लोग अपने घरों में मंगलमूर्ति गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और नियम निष्ठा पूर्वक 10 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी और विघ्न का नाश करने वाले हैं लेकिन अपनी चाहत के अनुसार गणेश की प्रतिमा या तस्वीर घर में लाएंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होंगी।

गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब घर लाएं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो। ऐसी मान्यता है कि दाएं हाथ की ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी प्रतिमा की पूजा से मनोकामना सिद्ध होने में देर लगती है क्योंकि इस तरह की सूंड वाले गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं।

गणेश जी प्रतिमा में यह भी ध्यान रखें कि गणेश जी सायुज और सवाहन हों। यानी गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत, अंकुश और मोदक होना चाहिए।

गणेश जी एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो और साथ में उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। शास्त्रों में देवताओं का आवाहन इसी रूप में होता है।

जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लानी चाहिए। नियमित इनकी पूजा से संतान के मामले में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती है।

घर में आनंद उत्साह और उन्नति के लिए नृत्य मुद्रा वाली गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। इस प्रतिमा की पूजा से छात्र और कला जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इससे घर में धन और आनंद की भी वृद्धि होती है।

गणेश जी आसान पर विराजमान हों या लेटे हुए मुद्रा में हों तो ऐसी प्रतिमा को घर में लाना शुभ होता है। इससे घर में सुख और आनंद का स्थायित्व बना रहता है। सिंदूरी रंग वाले गणेश को समृद्धि दायक माना गया है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थों एवं व्यावसायियों के लिए शुभ माना गया है।

वास्तु विज्ञान के अनुसार गणेश जी को घर के ब्रह्म स्थान (केंद्र) में, पूर्व दिशा में एवं ईशान में विराजमान करना शुभ एवं मंगलकारी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो। गणेश जी को दक्षिण या नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखें कि घर में जहां भी गणेश जी को विराजमान कर रहे हों वहां कोई और गणेश जी की प्रतिमा न हो। अगर आमने सामने गणेश जी प्रतिमा होगी तो यह मंगलकारी होने की बजाय आपके लिए नुकसानदेय हो जाएगी।

त्योहारों से पहले फीका हुआ पकवानों का स्वाद, चीनी के बढ़ते दाम ने बिगड़ा किचन का बजट

नई दिल्ली। एजेंसी

पहले टमाटर, फिर प्याज और अब चीनी की कीमतों ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। वहीं अभी इसमें राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। घरेलू चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और जानकारों की माने तो 2-3 महीनों तक ऊंची रहने की उम्मीद है , लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। स्थानीय चीनी की कीमतें पिछले तीन हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इसका कारण उत्पादन पर चिंता के साथ-साथ नाजुक बैलेंस शीट (30 सितंबर को 6 मिलियन टन स्टॉक बंद होने का अनुमान - त्योहार के महीनों में दो महीने की खपत के लिए मुश्किल से पर्याप्त) और देरी के कारण है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि त्योहारों में देरी (इसलिए श्रम की उपलब्धता) और मिलों द्वारा वसूली के स्तर को अनुकूलित करने के प्रयासों के कारण पेराई सीजन की शुरुआत से लेकर नवंबर के अंत (आमतौर पर मध्य

अक्टूबर) तक यह बना रहेगा। भारत तीन वर्षों से दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक रहा है और भारत के चीनी उत्पादन अनुमान और नगण्य/शून्य निर्यात की संभावना पर चिंताओं के कारण वैश्विक चीनी कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है,लेकिन निर्यात की कमी को देखते हुए इससे स्थानीय उत्पादकों को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। साथ ही, किसी भी आयात की कमी को देखते हुए स्थानीय कीमतों का वैश्विक कीमतों के साथ कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और सरकार अपने मासिक रिलीज तंत्र उपाय के माध्यम से स्थानीय कीमतों को प्रभावित करती है। पिछले महीने की शुरुआत में, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) ने एसएस24 (अक्टूबर 23-सितंबर 24) के लिए 31.7एमएनटी का प्रारंभिक चीनी उत्पादन (शुद्ध) अनुमान लगाया है। लेकिन, अगस्त'23 पूरे देश में शुष्क अवधि रही है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में (ये दोनों राज्य भारत के उत्पादन का 45-50 प्रतिशत हिस्सा हैं), इससे उत्पादन अनुमानों में और कटौती का खतरा पैदा हो गया है। 'हमारा अनुमान है कि एसए24ई के लिए भारत में चीनी का उत्पादन (शुद्ध उत्पादन, 4.5 मिलियन टन का डायवर्जन के बाद) 30 मिलियन टन होगा। हम ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश मे अगस्त में शुष्क मौसम देखने के बावजूद, महत्वपूर्ण सिंचाई के कारण मानसून में प्रभावित नहीं होता है, इसके लिए नदियों को धन्यवाद दिया जाता है। 'हम मौसमी कारकों (त्योहार की अवधि और इसलिए चीनी की कीमतों में वृद्धि) और आगामी सीजन (एसएस24ई) के लिए भारत के चीनी उत्पादन अनुमान पर बढ़ती चिंताओं के कारण चीनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण आशावाद लौट रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है,'हमारी राय में भारत का उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन (±/- 1 मिलियन टन) हो सकता है, जो घरेलू खपत 28-28.5 मिलियन टन से अधिक है। इसलिए, स्थिति आरामदायक है, निर्यात घोषणा, यदि कोई हो, मई 2024 के बाद ही आएगी (एक बार सीज़न खत्म होने के बाद), वैश्विक कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, लेकिन घरेलू चीनी की कीमतों पर इसका कोई खास असर नहीं है, चीनी की कीमतें, जो पिछले तीन हफ्तों में तेजी से बढ़ी हैं, स्थिर रहेंगी, हालांकि सरकार किसी भी तेज बढ़ोतरी पर रोक लगाएगी। वृद्धि का असर आसन्न राज्य/आम चुनावों पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा खाद्य मुद्रास्फीति पर भी पड़ा है।'' जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा कि चूंकि स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा पर वैश्विक सहमति है, इसलिए जी20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित जैव ईंधन गठबंधन को सही गंभीरता से लिए जाने की संभावना है। चूंकि भारत ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए भारतीय चीनी उद्योग को पेट्रोलियम उत्पादों के साथ इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के निर्णय से लाभ होगा। पिछले एक महीने के दौरान चीनी की कीमतों में करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, इससे चीनी कंपनियों के लिए संभावनाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अच्छी खबर पहले से ही है कि कई चीनी स्टॉक 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

ट्रेजर आइलैंड और इंदौर सेंट्रल मॉल ने 'द ग्लॉस बॉक्स' की घोषणा की

आगंतुकों के लिए ब्यूटी एवं वैलनेस की एक खास पेशकश

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

तेजी से बदलती दुनिया में ब्यूटी एवं वैलनेस यूं ही बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्द नहीं रह गए हैं बल्कि इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। अगर आप विविध प्रकार के कॉस्मेटिक्स और वैलनेस ब्रांडों के बीच से अपने मन मुताबिक उत्पाद चुनना चाहते हैं तो नेक्सस ट्रेजर आइलैंड और इंदौर सेंट्रल मॉल वो जगह है जहां आपको 8 सितंबर को आना चाहिए। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सितंबर माह में जानेमाने ब्यूटी ब्रांड शानदार डील्स प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा रिटेल प्लैटफॉर्म नेक्सस मॉल्स 'द ग्लॉस बॉक्स' की शुरुआत करने को बिल्कुल तैयार है। नेक्सस ब्रांड के पोर्टफोलियो में मौजूद सभी 17 मॉल्स के माध्यम से देश भर में एक अभूतपूर्व कॉस्मेटिक्स, ग्रूमिंग और वैलनेस कैम्पेन चलाई जा रही है जो ब्यूटी एवं वैलनेस इंडस्ट्री के भविष्य को नए आयाम देगी और आपके लिए सुंदरता का एक अनूठा अनुभव लेकर आएगी। 'द ग्लॉस बॉक्स' कैम्पेन 8 सितंबर से लाइव है और इसका लक्ष्य है ब्यूटी एवं वैलनेस के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना। इसमें बहुत से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वैलनेस ब्रांड, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी ऐक्सपर्ट और ब्लॉगर भाग लेंगे और नेक्सस मॉल्स पोर्टफोलियो में मौजूद सभी मॉल्स में आगंतुकों को एक शानदार अनुभव प्राप्त होगा। प्रीमियम कॉस्मेटिक्स और वैलनेस उत्पादों का सावधानी पूर्वक तैयार किया गया संग्रह सबसे लोकप्रिय ब्रांडों को नेक्सस ट्रेजर आइलैंड और इंदौर सेंट्रल मॉल में एकजुट करने जा रहा है। बाकी ब्यूटी फैस्ट के मुकाबले जो चीज 'द ग्लॉस बॉक्स' को अलग करती है वह है 'फिजिटल' कन्वर्ज्ड ऐक्सपीरियेंसिस का समूह जिसे इस प्रकार क्यूरेट किया गया है कि उपभोक्ताओं को स्किनकेयर, मेकअप, हेयरकेयर, स्पा, वैलनेस आदि के सबसे जानेमाने ब्रांडों को महसूस कर सकें। ग्राहक लाइव डैमॉन्स्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं अथवा अपने जैसे विचार वाले लोगों से कनेक्ट कर के मजेदार अनुभव ले सकते हैं। इस कैम्पेन के तहत जो कार्यक्रम होने हैं उनमें शामिल है- विशेषज्ञों के साथ स्पेशल मास्टर क्लास सैशन जो ब्यूटी एवं वैलनेस इंडस्ट्री के बदलाव और उसके असर पर चर्चा करेंगे तथा संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित नये रुझानों व तकनीकों पर बहुमूल्य जानकारी साझा करेंगे।

आईएचसीएल ने इंदौर में आईएचसीएल सेलेक्शंस होटल 'वॉव क्रेस्ट' के खुलने की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी (आईएचसीएल) ने इंदौर (म.प्र.) में आईएचसीएल सेलेक्शंस होटल 'वॉव क्रेस्ट' के खुलने की घोषणा। इंदौर शहर के हृदय स्थल में स्थित यह होटल इस कमाल के शहर का आकर्षक प्रवेशद्वार है जहां से समृद्ध इतिहास और जीवंत वर्तमान वाले इस शहर में घूमा जा सकता है। आईएचसीएल की कार्यकारी उपाध्यक्ष (होटल ओपनिंग्स व कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशंस) सुश्री दीपिका राव ने कहा, ''वॉव क्रेस्ट-आईएचसीएल सेलेक्शंस के द्वार खोलते हुए हम बहुत खुश हैं। इस होटल के खुलने के साथ ही इंदौर में सेलेक्शंस ब्रांड की मौजूदगी हो गई है जो कि एक अहम कारोबारी शहर है। इस शुरुआत के साथ आईएचसीएल मध्य प्रदेश में विस्तार कर रही है और अब हमारे सभी ब्रांड राज्य में जगह बनाएंगे।'' 125 कमरों का यह होटल देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट से, शहर के औद्योगिक केंद्र से और प्रमुख स्थलों से कुछ ही मिनटों की ड्राइविंग दूरी पर मौजूद है। इसका आधुनिक डिजाइन होटल के सुंदर इंटीरियर एवं कमरों व सुइट्स की आमंत्रण देती साज-सज्जा में झलकता है। यहां डाइनिंग के विकल्पों के साथ अतिथिगण खानपान का आनंद ले सकते हैं। ऑल-डे डाइनर कॉन्स्टेलेशन में स्थानीय एवं दुनिया में मशहूर व्यंजन परोसे जाते हैं जबकि नज़्म में नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर के व्यंजन उपलब्ध हैं। अल फ्रेस्को धुआँ में आप हल्का-फुल्का खानपान का मजा ले सकते हैं, ट्वाईलाइट में रिलेक्स कर सकते हैं या फिर केक मी अप में पेस्ट्री का लुत्फ ले सकते हैं।

हिंदुस्तान पेंसिल्स ने घोटालेबाजों के खिलाफ उठाया कदम फर्जी पेंसिल पैकिंग नौकरी पर जन-जागरूकता की अपील

आईपीटी नेटवर्क

1958 में स्थापित पेंसिल और स्टेशनरी बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भोली-भाली आम जनता को फर्जी नौकरी के नाम पर धोखे से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में कंपनी को पता चला है कि उनके प्रतिष्ठित पेंसिल ब्रांड नटराज और अप्सरा के नाम पर अनुचित तरीके से नौकरी के फर्जी प्रस्ताव देकर धोखाधड़ी के मामले तेजी से फैल रहे हैं। हिंदुस्तान पेंसिल्स के प्रेसिडेंट, श्री प्रदीप उघाड़े ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि हम अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण स्टेशनरी उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। यह देखकर हमें बहुत दुख होता है कि नौकरी की तलाश करने वाले मासूम लोगों को शिकार बनाने के लिए घोटालेबाजों द्वारा नटराज और अप्सरा ब्रांड के नाम का दुरूपयोग किया जा रहा है। धोखाधड़ी की इन गतिविधियों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमारा यह दृढ संकल्प है कि आम जनता को पूरी जानकारी प्राप्त हो और वे संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहें।' यह घोटालेबाज खुद को नटराज और अप्सरा के प्रतिनिधि के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वे नटराज और अप्सरा के रजिस्टपर्ड ऑफिस के पते और साथ ही उनके कर्मचारियों की तस्वीरों का उपयोग करके भोली भाली जनता को धोखा दे रहे हैं। वे इन लोगों को गूगल, लिंक्डइन, वॉट्सऐप और अन्य ऑनलाइन प्लैटफॉर्म सहित इन्टरनेट पर विभिन्नग माध्यमों से तथाकथित रूप से घर बैठे पेंसिल पैकिंग की नौकरी का झाँसा देकर ठग रहे हैं। इन गुमराह करने वाले प्रस्तावों के कारण कई दुर्भाग्यपूर्ण मामले सामने आए हैं जिसमें नौकरी की तलाश करने वाले मासूम लोग इन घोटालों का शिकार हुए हैं और उन्हें पैसों का नुकसान हुआ है। साल 1958 से उन्नलत तकनीक के माध्यम से पेंसिल्स और अन्य स्टेशनरी के निर्माण में सबसे आगे नटराज और अप्सरा ने घर बैठे पेंसिल पैकिंग की नौकरी के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को कभी अनुमति नहीं दी है। घर बैठे नौकरी पाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले उम्मीदवारों और आम जनता को कंपनी यह बताना चाहती है कि नटराज और अप्सरा में भर्ती एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। कंपनी साफ-साफ शब्दों में यह बता रही है कि नटराज और अप्सरा ने किसी भी वेबसाइट या संस्था को यह अधिकार नहीं दिया है कि वे अपने वेबसाइट पर कंपनी में भर्ती के लिए कोई आवेदन स्वीकार करें।

क्रॉम्पटन को पीएम कुसुम स्कीम के तहत सौर पम्पों के लिये महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के भरोसेमंद ब्रांड और पम्पस में अग्रणी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हरियाणा राज्य में पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्पों का एक महत्वपूर्ण काम मिला है। कंपनी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा और एचएआरईडीए द्वारा 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर सबमर्सिबल वाटर पम्पिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापन एवं आरंभ का शुरूआती कार्य-आदेश मिला है। यह उपलब्धि एसईसीआई और एमएनआरई के नेतृत्व में एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका लक्ष्य है पूरे भारत में 6.6 लाख पंपों को बदलकर नये कनेक्शन लगाना। इस अवसर पर बात करते हुए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वाईस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड पम्पस रजत चोपड़ा ने कहा क्रॉम्पटन में हमें अपने उपभोक्ताओं के जीवन को समृद्ध बनाने वाले नवाचार लाने की अपनी विरासत पर गर्व है। पानी देने और अनिवार्य वस्तुओं का अबाध प्रवाह सुनिश्चित करने में पम्प एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। क्रॉम्पटन महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों में निविदा की प्रक्रिया में सक्रिय है। एसईसीआई और एमएनआरई के पर्यवेक्षण में किये गए आरंभिक बुनियादी कार्य का स्वरूप अंतिम कार्यान्वयन चरण के लिए बदल कर सम्बंधित राज्य की नोडल एजेंसी-एचएआरईडीए (हरियाणा), एमईडीए, एमएसईडीसीएल (महाराष्ट्र), एमपीयूवीएनएल (मध्य प्रदेश) और आरएचडीएस, आरयुवीवीएनएल (राजस्थान) हो गया। क्रॉम्पटटन इस कार्य-आदेश के साथ एचएआरईडीए के साथ अपना परिचालन आरंभ करने के लिये तैयार है, वे राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए समान रूप से तैयार हैं।

कोका-कोला इंडिया का प्रोजेक्ट जलधारा

मप्र में बदल रही है लोगों की ज़िंदगी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोका कोला के लिए जल प्रबंधन लम्बे समय से एक व्यावसायिक अनिवार्यता रहा है। कंपनी अपने बेवरिजेज के लिए जहां-जहां से एग्री प्रोडक्ट की खरीदारी कर लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, उन सभी जगहों पर वर्ष 2030 के आते-आते अपने व्यवसाय, समुदायों और प्रकृति के लिए जल सुरक्षा हासिल करने हेतु वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर एक नई समग्रता पूर्ण रणनीति की घोषणा की गई थी।

सितंबर, 2023 भारत में कोका-कोला अपने वैश्विक तथा स्थानीय फाउंडेशन के माध्यम से जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन और जल सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखती है। पूरे देश में जल की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक जल प्रबंधन रणनीतियों और संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से जल के संरक्षण और पुनर्मूर्ति के लिए विभिन्न एनजीओ, नागरिक संगठनों और स्थानीय निवासियों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से कंपनी ने वर्ष 2007 में आनंदन कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की थी। उसके बाद से अभी तक भारत में परिचालन के दौरान उपयोग किये गए जल के 100ज्ञ से अधिक की पुनः पूर्ति करने में कंपनी सफल रही है।

भारत में भूमिगत जल एक संकटग्रस्त स्रोत है। हम भूमिगत जल के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। 60ज्ञ से ज्यादा सिंचित कृषि और 85ज्ञ पीने का पानी भूमिगत जल पर निर्भर है। नतीजतन, अति दोहन के कारण बढ़ती संख्या में भूमिगत जलवाही स्तर अरक्षणीय (अनसस्टेनेबल) स्तर तक पहुँच रहे हैं। कृषि के चिरस्थायित्व, दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा, आजीविका और देश की आर्थिक उन्नति के लिए इसके निहितार्थ गंभीर होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो देश की एक तिहाई से भी ज्यादा फसल के खतरे में पड़ने की आशंका है। इस यथास्थिति को तत्काल बदलने की जरूरत है।

अपने जल प्रबंधन प्रोजेक्ट के माध्यम से, कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन, देश के सूखाग्रस्त इलाकों में लाखों लोगों को पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराती रहेगी। मध्यप्रदेश में यह जल परियोजना बेहतरीन परिणाम दे रही है, जिसकी वजह से काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। इससे लाभान्वित होने वाले लोग काफी खुश हैं जो पहले जल की अत्यधिक कमी से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, क्योंकि उनके पास अब काफी प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को देश के जल की कमी वाले जिले घोषित किए थे, क्योंकि इन इलाकों में जल की गंभीर समस्याएं थीं और बड़ी संख्या में पलायन हो रहा था। मानव विकास क्रम में काफी पीछे छूट गए अलीपुर जिले के निवासियों ने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया।

एथर एनर्जी ने हीरो मोटोकॉर्प और जीआईसी से 900 करोड़ रुपये एकत्रित किए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर केंद्रित अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों में से एक, एथर एनर्जी ने राइट्स इश्यू की मदद से अपने वर्तमान शेयरधारकों हीरो मोटोकॉर्प और जीआईसी से 900 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। इस फंड का उपयोग एथर अपने नए उत्पाद लॉन्च करने एवं अपने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए करेगा। एथर ने वित्त वर्ष 2023 में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि की है। वित्तवर्ष 2023 में कंपनी का राजस्व बढ़कर 1,783 करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्तवर्ष 2022 में 408 करोड़ रुपए से 4.4 गुना ज़्यादा है। एथर ने रिटेल में भी

तज़ा स ावस्तार ाकया ह, आर आज इसके पास पिछले साल 30 स्टोर के मुक़ाबले 4 गुना ज़्यादा, यानि 130 स्टोर हैं। वर्तमान में एथर एनर्जी के पास 100 से ज़्यादा शहरों में 200 से अधिक रिटेल टचप्वाइंट हैं और 1,500 से ज़्यादा एथर ग्रिड के साथ इसके पास इलाक्ट्रक स्कूटरा क ालए सबस बड़ा सार्वजनिक फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क है। एथर ने हाल ही में अपने फ्लैगशिप 450ॅ को 2.9 ॅ और 3.7 ॅ बैटरी विकल्पों में उतारकर एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर 450ए के साथ अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, ताकि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाजार में ज़्यादा बड़े ग्राहक वर्ग की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर कई नए बदलावों के साथ आते हैं, जिसमें डीपव्यू ऊश डिस्प्ले, नया स्विचगियर, फॉलसेफ ऊश, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ईएसएस), और बेहतर रेंज के लिए कोस्टिंग रीजेन शामिल हैं। इस बारे में एथर एनर्जी के सीईओ और को-फाउंडर, तरुण मेहता ने कहा, 'हमारे राइट्स इश्यू को काफ़ी सहयोग मिला। शेयरधारकों का यह विश्वास देखकर हमें बहुत खुशी मिली है। पिछले कुछ सालों में दिख गया है कि भारत में ईवी की ओर कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो सकता है, जिसका नेतृत्व इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा होगा।

डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड

निवेशकों को अधिक वैल्यूएशन पर भी निवेश के विकल्प

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

लंबे समय में निवेश से अच्छा रिटर्न पाने के लिए इंवेस्टमेंट को लगातार बनाए रखने की जरूरत होती है। हालांकि, जिस प्रकार अधिकतर निवेशक भावनाओं में आकर फैसले लेते हैं और बाजार के ऊपर पर ज्यादा निवेश करते हैं और मार्केट में गिरावट के समय पैसे की जरूरत नहीं होने पर भी बाजार से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे में निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन काम है। टिके रहने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कई प्रकार के मटेरियल की जरूरत होती है, जिनमें से हर कोई अपनी अच्छी-अच्छी बातें लाता है। इसी तरह, एक उन निवेशकों को अलग-अलग प्रकार के एसेट क्लास की जरूरत पड़ती है, जो मजबूत पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं के खिलाफ मजबूती से खुद को टिकाए रखने में मदद मिल सके। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड (डीएसपी एमएएएफ) के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक ओपन-एंडेड स्कीम है और जिसका उद्देश्य निवेशकों को इक्विटी की तरह लंबी अवधि का रिटर्न ऑफर करना है। लेकिन साथ में बाजार में गिरावट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त लचीलापन (रेजिलिएंस) भी ऑफर करना है।

रुपया दो पैसे गिरकर 82.97 प्रति डॉलर पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को दो पैसे टूटकर 82.97 (अस्थायी) प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने से रुपये की धारणा कमजोर हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू बाजार में सकारात्मक धारणा और भारत के बेहतर वृहद आर्थिक आंकड़ों की वजह से रुपये की गिरावट सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.92 पर खुला। दिन में कारोबार के दौरान यह 82.89 से 82.99 प्रति डॉलर के दायरे में घूमने के बाद अंत में अपने पिछले बंद भाव से दो पैसे की गिरावट के साथ 82.97 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 82.95 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 104.79 पर रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.58 प्रतिशत बढ़कर 92.59 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 1,047.19 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।